यूएसएड

विकास यात्रा का अंतिम चरण

यह मजबूत रिश्ता पांच दशक से भी ज्यादा पुराना है। समय के साथ भारत को अमेरिकी सहायता के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। 50 साल पहले के अकाल पीड़ित देश के लिए खाद्यान्न भेजने से लेकर आज के सहकारी गठजोड़ तक का यह सफर निश्चय ही भारत को अपने विकास का आखिरी चरण पूरा करने में मदद करेगा। अमेरिका-भारत संबंध पहले के मुकाबले अधिक गहरे और मजबूत हो गए हैं।

भारत के लिए सन् 1951 में घरेलू खाद्यान्न की कमी से निबटने के लिए बीस लाख टन गेहूं की खरीद के वास्ते कर्ज लेने के तौर पर जिसकी शुरुआत हुई, वह युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) के नेतृत्व में भारतीय साझीदारों के सहयोग से व्यापक कार्यक्रम बन गया है। 2004 में यूएसएड आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और ईक्विटी सहायता में 610 करोड़ रु. (13.50 करोड़ डॉलर) निवेश करेगा। अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच सामरिक साझीदारी की। दुनिया के दो बड़े लोकतंत्रों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। विकास की मौजूदा पहल हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव की मिसाल है, जो बढ़ती दोस्ती और साझा दूरदृष्टि में से एक है। यूएसएड जलवायु में परिवर्तन से निबटने, एचआइवी/एड्स और संक्रामक रोगों से लड़ने, परिवार के स्वास्थ्य की देखरेख और बच्चों की उत्तरजीविता, स्वच्छ ऊर्जा और जल की उपलब्धता, मुक्त वित्तीय बाजार और संवेदनशील वर्गों खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए अवसर जैसे विश्वव्यापी मुद्दों से निबटने के लिए सार्वजनिक और निजी संसाधन जुटाता है।

यूएसएड की दीर्घकालिक योजना है कि भारत का सभ्य समाज अमेरिकी आर्थिक सहयोग के बिना विकास संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए अमेरिकी निजी साझीदारों के साथ काम करे। विकास संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक नए मॉडल—एक ''साझा कोष'' का परीक्षण चल रहा है। 2015 में अमेरिकी सहायता खत्म होने के बाद यह कोष निजी, स्वायत्त हो जाएगा जो बाकी चुनौतियों से निबटने के लिए अमेरिकी और भारतीय संस्थाओं को जोड़ेगा। यह अवधि भारत के प्राथमिक विकास लक्ष्य की अवधि से मिलती है: भारत को 2015 तक गरीबी की दर आधी करनी है और उसके बाद उसे फौरन खत्म करना है।

यूएसएड मौजूदा सामाजिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए (राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर) भारत सरकार, स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ साझीदारी करता है। ये समस्याएं हैं: जच्चा-बच्चा की अल्प उत्तरजीविता की दर; बढ़ती जनसंख्या; रोग और कुपोषण के अधिक मामले; जल और वायु प्रदूषण; और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए सीमित अवसर।

अमेरिका-भारत के संबंधों में नई गति के मद्देनजर अमेरिका ऐसी गतिविधियों में भी निवेश कर रहा है जिनमें दोनों देशों के साझे हित पर ध्यान तथा व्यापक स्तर पर

यूएसएड ने भारतीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार से साझेदारी कर रखी है

संदीप बिस्वास/साभारः यूनीसेफ

1950-1999

यूएसएड की मदद का बदलता स्वरूप

■ 1950 का दशकः 1951 में 20 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए भारत को ऋण के साथ मदद की शुरुआत।

■ 1960 का दशकः भारत की ''हरित क्रांति'' को व्यापक मदद, कृषि अनुसंधान, सुविधाओं और सूचनाओं की साझीदारी में निवेश, जिनसे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में मदद मिली।

■ 1970 का दशकः यूएसएड ने भारत-पाकिस्तान युद्ध की वजह से खाद्यान्न सहायता को छोड़कर अन्य कार्यक्रम स्थगित किए। 1978 में सहायता फिर बहाल।

■ 1980 का दशकः प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर। उपग्रह तंत्र के विकास समेत विभिन्न परियोजनाओं में गठबंधन। अमेरिका की ऋण गारंटी से भारत की निजी आवास वित्त व्यवस्था को समर्थन।

■ 1990 का दशकः आर्थिक विकास, एचआइवी/एड्स और दूसरे संक्रामक रोगों के निर्मूलन के प्रयास, और जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर जोर। अमेरिकी सहायता से भारत का पहला सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी बनाने में मदद मिली और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के महत्वपूर्ण शोध अध्ययन के लिए पैसा मिला।

संपन्नता तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जाता है:

■ विस्तृत पूंजी बाजार और वित्तीय रूप से स्वस्थ राज्य सरकारें;

■ बिजली की उपयोगिता को फायदेमंद बनाना और सब्सिडियों के लिए सार्वजनिक संसाधनों को कम करना (जिनका प्रयोग सामाजिक बुनियादी संरचना के लिए हो सके);

■ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से ऊर्जा की क्षमताओं में सुधार जिससे विकास को ''ईंधन'' मिले और संसाधन संरक्षित हों;

■ प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदाओं से निबटने के लिए विस्तृत आपदा प्रबंधन व्यवस्था;

■ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए और अधिक वैज्ञानिक सहयोग;

■ खाद्यान्न सहायता को स्वास्थ्य और एचआइवी रोकथाम से जोड़कर जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को पोषण मुहैया कराने के लिए सरकार के साथ सहयोग बढ़ाना;

■ महिलाओं और लड़कियों में साक्षरता बढ़ाने, और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई शैक्षिक विधियों का प्रयोग बढ़ाना; और

■ विकराल रूप धारण कर रही महामारी को खत्म करने के लिए एचआइवी/एड्स रोकथाम और देखभाल को भरपूर समर्थन।

अमेरिकी कोष से सूखा राहत में मदद दी गई

प्रमोद पुष्करणा/इंडिया टुडे

भारत अपने विकास के सफर के आखिरी चरण में है।

विकास के लिए पैसा उगाहने का तरीका

भारत की एक-तिहाई आबादी शहरी इलाकों में रहती है। इस देश में बहुत तेजी से शहरीकरण भी हो रहा है। एक-तिहाई से भी कम घरों में शौचालय हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए हर साल 60-80 करोड़ डॉलर की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 10 करोड़ डॉलर ही उपलब्ध हैं।

भारत को पूंजी बाजार और बुनियादी संरचना के विकास के बीच की खाई को पाटने में मदद के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करना निजी वित्त जुटाने का एक तरीका है। विकसित ऋण बाजार से देश को विकास का एजेंडा पूरा करने में मदद मिलती है।

जनवरी 1998 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) तब महानगरीय

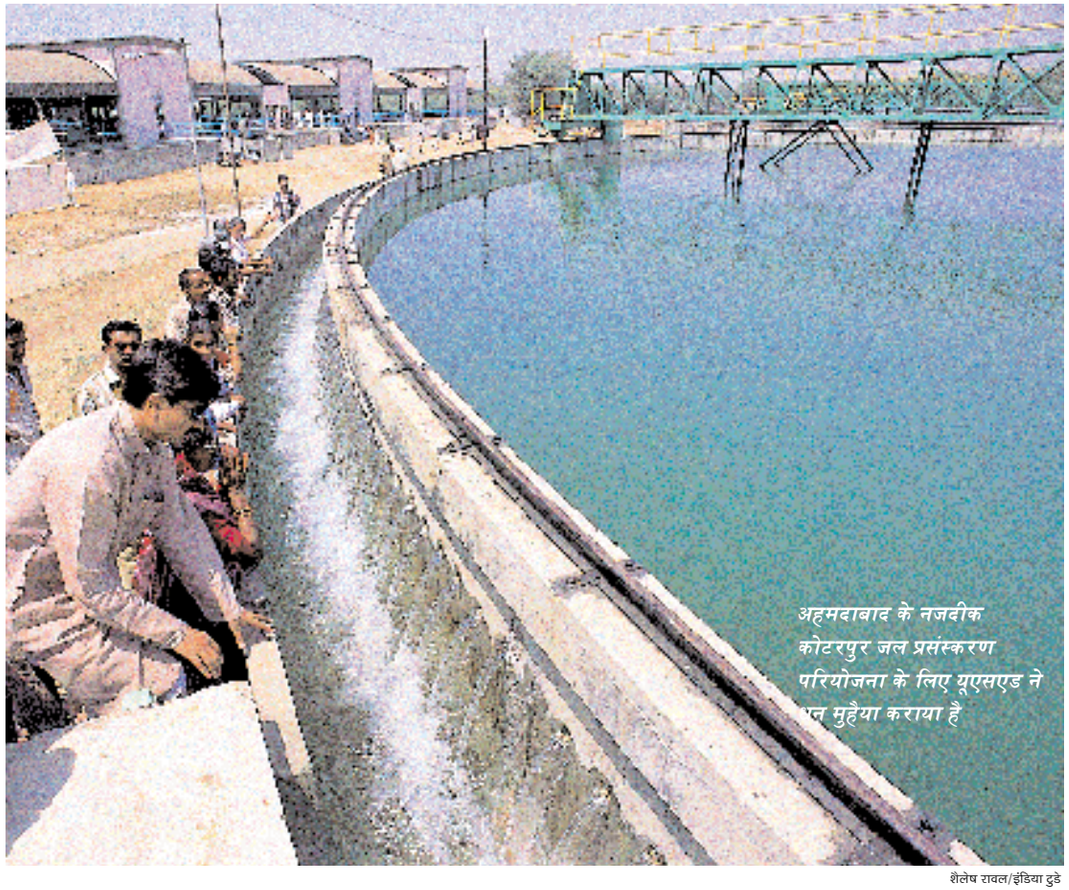

अहमदाबाद के नजदीक कोटरपुर जल प्रसंस्करण परियोजना के लिए यूएसएड ने न मुहैया कराया है

शैलेष रावल/इंडिया टुडे

वित्तीयन के मामले में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया जब उसने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं की खातिर पैसा उगाहने के लिए 100 करोड़ रु. (2.1 करोड़ डॉलर) के बॉन्ड जारी किए। एशिया में पहली बार किसी राज्य सरकार की गारंटी के बगैर म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए। एएमसी बॉन्ड के कुछ हिस्से न केवल शेयर बाजार में बेचे गए बल्कि उनके लिए जरूरत से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया। इस प्रयोग की सफलता ने जाहिर कर दिया कि भारत में बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए पैसे की खातिर म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करना कारगर होता है और यह कि इस मॉडल को देश के दूसरे हिस्से में भी लागू किया जा सकता है।

भारत में पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने योग्य स्थिति तैयार करने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पांच साल पहले एएमसी कर्ज तले दबा था और उसका घाटा 35 करोड़ रु. (60 लाख डॉलर) पहुंच गया था। तभी यूएसएड और उसके साझीदार उसकी मदद को आगे आए और एएमसी का वित्तीय प्रबंधन तथा बही-खाता व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित करने में मदद की। सिर्फ तीन साल के भीतर न सिर्फ

2000 के बाद

■ 2000 के बादः यूएसएड ने राज्य और केंद्र स्तर पर वित्तीय सुधारों में मदद की। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सुधारने और संक्रामक रोगों के उन्मूलन का काम जारी रहा। निवेश के नए क्षेत्रों–ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, आपदा प्रबंधन व्यवस्था और शिक्षा के जरिए बाल श्रम पर रोक शामिल है। महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में भी काम किया जा रहा है।

यूएसएड भारत में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन और वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार पर जोर दे रहा है।

एएमसी की स्थिति बेहतर हो गई बल्कि इसे क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज़ ऑफ इंडिया (क्रिसिल) नामक एजेंसी ने 'एए' की ऊंची रेटिंग दी। इससे प्रभावित होकर भारत के आठ नगर निगमों ने पूंजी बाजारों से पैसा उगाहा है। यूएसएड द्वारा शुरू की गई ''एकीकृत वित्तीय योजना'' के तहत तमिलनाडु में छोटे स्थानीय निकायों ने अपनी जल और साफ-सफाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने के लिए संयुक्त रूप से बॉन्ड जारी किए हैं, और बंगलोर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की आठ नगरपालिकाओं में भी ऐसा ही नुस्खा अपनाया जा रहा है।

रोशन राहें

अमेरिकी सहायता का मुख्य क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के तहत बिजली का बढ़िया वितरण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को आगे बढ़ाना और पुन: प्रयोग होने

शरद सक्सेना/इंडिया टुडे

निर्बाध बिजली आपूर्ति में साझीदार नोएडा पावर कंपनी लि.

वाली प्रौद्योगिकियों का प्रयोग है। यूएसएड-पोषित साझीदार, नोएडा पावर कंपनी लि. (एनपीसीएल) ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक बिजली वितरण व्यवस्था के लिए आदर्श बन गई है। यूएसएड से 2.8 करोड़ रु. (6,00,000 डॉलर) के प्रारंभिक ऋण लेकर कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली वितरण में सुधार कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा वितरण तंत्र बिजली चोरी, मनमानी सब्सिडी और अधिक खपत वाले पंपों की वजह से बदहाल है। एनपीसीएल के सीईओ प्रबीर नियोगी कहते हैं कि उनकी कंपनी नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के नए तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दुरुपयोग को कम करने का प्रयास कर रही है। नतीजा: लगातार बिजली की आपूर्ति के साथ ही आर्थिक और सामाजिक विकास का दायरा बढ़ रहा है।

एनपीसीएल ने उच्चदाब वाली लाइनों और कम वोल्टेज वाले इंसुलेटेड तारों का जाल बिछाकर अबाध बिजली-आपूर्ति की व्यवस्था की है। बिलिंग और बिजली की खपत मापने की व्यवस्था में सुधार के साथ ही उपभोक्ता सेवा कंपनी का ट्रेडमार्क बन गया। इसके बाद एनपीसीएल ने ग्रामीणों के बीच अविश्वसनीय बिजली की ''असली कीमत'' और ऊर्जा संरक्षण के फायदों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन की मदद ली। नतीजा: उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्रामीणों ने मीटर लगवाने में दिलचस्पी ली और सब्सिडी के दौर में होने वाली बिजली कटौती की बजाए अब निर्बाध बिजली पा रहे हैं। किसानों ने सिंचाई के लिए ऐसे पंप लगाए हैं जिनमें बिजली की खपत ज्यादा नहीं है।

अनुभव से जाहिर है कि अगर बेहतर वाणिज्यिक सेवा के साथ बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो तो भारतीय उपभोक्ता गैर-रियायती बिजली की कीमत चुकाएंगे। सब्सिडी के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दूसरी सामाजिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश सीमित हो जाता है।

भारत की सलामती

सन् 1999 में ओडीसा में आया चक्रवाती तूफान और 2000 का गुजरात भूकंप भारत के लिए प्रमुख आपदाएं थीं। उनमें करीब 22,000 लोग मारे गए और 30 लाख से अधिक घर तबाह हो गए। उन आपदाओं के समय दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया जताई और वही अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की शुरुआत थी।

अमेरिका और भारत के बीच 72 करोड़ रु. (1.6 करोड़ डॉलर) के द्विपक्षीय समझौते हुए जिनके तहत भारत के लोगों और देश की विकास प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए दोनों लोकतंत्रों के बीच आपदा प्रबंधन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवस्था निर्माण में सहयोग शामिल है। यह संबंधों में बदलाव के क्षेत्र में मील का पत्थर है।

इस पहल के तहत भारत में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन

भावी परिदृश्य

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यूएसएड कई सार्वजनिक और निजी साझीदारी को समर्थन दे रहा है

- आर्थिक विकास: नए निवेशकों को बाजारों में लाना, वित्तीय फैसलों के पूर्वानुमान और उनके विश्लेषण में राज्य सरकारों की मदद करना, शहरी विकास और आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के लिए धन मुहैया कराने की गतिविधियां।
- स्वास्थ्य: परिवार के स्वास्थ्य की देखरेख, गरीब माताओं और बच्चों को भोजन मुहैया कराने और रोगों से लड़ने के लिए उनकी रोगरोधी क्षमता बढ़ाने के प्रयास।
- आपदा प्रबंधन: आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए अमेरिका के विशेषज्ञ अपने भारतीय समकक्षों को आपदा प्रबंधन की जानकारी देते हैं।
- बिजली और पर्यावरण: व्यावहारिक उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति बढ़ाने तथा आर्थिक लाभ उठाने के लिए जरूरी है। इसके मद्देनजर स्वच्छ ऊर्जा और जल मुहैया कराने की पहल की जा रही है।
- ईक्विटी: अमेरिकी सहायता से कमजोर लोगों के लिए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लड़कियों को शिक्षा और शिक्षा का स्तर सुधारा जा रहा है, बाल श्रम, मानव तस्करी रोकी और पारिवारिक अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा रही है।

अमेरिका और भारत सूखे (नीचे) और भूकंप (सबसे नीचे) जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग कर रहे हैं

प्रमोद पुष्करणा/इंडिया टुडे

बंदीप सिंह/इंडिया टुडे

व्यवस्था को विस्तृत बनाकर उसे और मजबूत करना है। यूएसएड अपने नेतृत्व में अमेरिकी विशेषज्ञों की उनके भारतीय समकक्षों के साथ विधियों, उपायों और प्रौद्योगिकियों की जानकारी की साझीदारी कराता है। यही नहीं, यूएसएड आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए उसमें फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, यू.एस. फॉरेस्ट सर्विस, नेशनल ओशियनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यू.एस. जियोलॉजिकल सर्वे समेत नए अमेरिकी साझीदारों को शामिल करता है।

प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुक्सान और उसके कारणों की विस्तृत जानकारी और विश्लेषण से भविष्य में उसके प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यूएसएड और भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने की खातिर प्राथमिकताएं तय करने और मौजूदा उपायों में सुधार करने के लिए साझीदार के रूप में काम कर रहे हैं। इस सहयोग की मुख्य विशेषताएं हैं: प्राकृतिक या मानवजनित आपदा की स्थिति में भारत की फौरी प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए यू.एस. इनसीडेंट सिस्टम की विशेषताओं को भारतीय माहौल के अनुरूप अपनाना; मौसम संबंधी (जैसे बाढ़, चक्रवात या सूखा) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना; और जिन इलाकों में प्राकृतिक या मानवजनित आपदा की सर्वाधिक आशंका है, वहां के समुदायों को उसके लिए पहले से तैयार करना।

एच.के. राजशेखर/इंडिया टुडे

तमिलनाडु में एक एचआईवी-एड्स परामर्श केंद्र

एड्स के खिलाफ जंग में तेजी

भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में तमिलनाडु में सामने आया था। आज 45 लाख भारतीय एचआईवी से संक्रमित हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के बाद सर्वाधिक संख्या है। हालांकि यह गंभीर स्थिति है लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं—रोकथाम के प्रयासों के कारण एचआईवी/एड्स से सर्वाधिक प्रभावित तमिलनाडु में संक्रमण की दर स्थिर हो गई है। यूएसएड ने तमिलनाडु में अपनी एड्स प्रीवेंशन एंड कंट्रोल (एपीएसी) योजना 1992 में शुरू की थी। यह अमेरिका-भारत की द्विपक्षीय पहल है। इस योजना को वॉलंट्री हेल्थ सर्विसेज संचालित कर रही है। ग्रामीण इलाकों में अधिक जोखिम वाले समूहों (ट्रक चालकों और वेश्याओं) में एचआईवी के संक्रमण को रोकने पर ध्यान दिया जाता है।

स्वयंसेवी संगठनों को समर्थन, अनुसंधान और तमिलनाडु सरकार के साथ सहयोग से एचआईवी के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई है। नतीजे साफ दिख रहे हैं: कुल मिलाकर एचआईवी संक्रमण की दर धीरे-धीरे कम हो रही है; ट्रक चालकों के बीच कंडोम का प्रयोग 50 फीसदी से बढ़कर 84 फीसदी हो गया है, और वेश्याओं के बीच उसका प्रयोग और भी (88 फीसदी) बढ़ गया है। पहली बार 1992-2002 के दौरान एड्स की रोकथाम के लिए 48 करोड़ रु. (1 करोड़ डॉलर) की राशि दी। उसके बाद अमेरिका ने 2007 तक के लिए 70 करोड़ रु. (1.55 करोड़ डॉलर) अतिरिक्त सहायता की घोषणा की है। ■

निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अमेरिका और भारत के आपसी संबंध विकसित होकर गतिशील गठजोड़ बन गया है।